प्रेषक.

सुशांत पटनायक अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 🗷 🔿 अक्टूबर, 2012

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के आयोजनेत्तर पक्ष की ''वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति'' योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–1)के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19जून, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की "वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति" योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹7,55,000/-(₹ सात लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- 1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुमाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमित/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
- वजट प्राविधान किसी भी लेखा शिर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
- 3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
- 4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी०एम०-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
- 5. बी०एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
- 6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
- 7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

- 8. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली हाय.
- 9. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- 10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमित/स्वीकृति ली जाय.
- 11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
- 12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- 13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id-\$1210270199 है. आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-00-वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा । इस प्रयोजन हेतु Online Bugdet Allotment की हार्ड कापी भी संलग्न की जा रही है।

मानक मद	चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित आय—व्ययक	निर्गत वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान में प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
04-यात्रा व्यय	1	0	0
07-मानदेय	200	0	200
08-कार्यालय व्यय	60	0	60
09-विद्युत देय	1	0	0
10-जलकर/जल प्रभार	1	0	0
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	20	0	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25	0	25
15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	150	0	150
16-व्यवसायिक सेवा के लिए भुगतान	1	0	0
१७-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	250	0	250
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	50	0	50
योग-	759	0	755

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ सात लाख पचपन हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश सं0- सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19जून, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के कम में निर्गत किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय.

(सुशांत पटनायक) अपर सचिव

संख्या- (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
- 2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
- 3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
- 4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
- 5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोच्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
- 6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
- 7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
- 8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन्, देहरादून.
- 9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
- 10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
- 11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
- 12 प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
- 13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से, (सुशांत पटनीय

अपर सचिव

बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - S1210270199

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1210270199

आवंटन पत्र दिनांक - 30-Oct-2012

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक -

2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

00 - वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति

01 - वानिकी

04 - वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति

			Non Plan Voted	
मानक मद का नाम	 पूर्व में जारी 	वर्तमान में जारी	योग	
07 - मानदेय	0	200000	200000	
08 - कार्यालय व्यय	0	60000	60000	
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	20000	20000	
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर	0	25000	25000	
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट	0	150000	150000	
17 - किराया, उपशल्क और कर-स	0	250000	250000	
22 - आतिष्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	50000	50000	
	0	755000	755000	

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

755000

